भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.3421

12 मार्च 2026, को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025

3421. श्री टी. आर. बालूः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट से यह पता चला है कि दस लाख से अधिक आबादी वाले अधिकांश शहर स्वच्छता के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जिन शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, वे भी साफ-सफाई की खराब स्थिति का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे नगर निगमों को प्रदान की गई विशेष वित्तीय सहायता के साथ-साथ क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों को अच्छी जीवन दशाओं का आश्वासन दिया जाए?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय वर्ष 2016 से एक वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण - स्वच्छ सर्वेक्षण कर रहा है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में शहरों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2011 की जनगणना के अनुसार, दस लाख से अधिक आबादी वाले 47 यूएलबी हैं, जिनमें से 44 यूएलबी का मूल्यांकन किया गया था (पश्चिम बंगाल के 3 यूएलबी ने एसएस 2024-25 में भाग नहीं

लिया)। मूल्यांकन किए गए 44 शहरों में से, 42 शहरों ने राष्ट्रीय औसत से अधिक जबकि 2 शहरों ने राष्ट्रीय औसत से कम अंक प्राप्त किए हैं।

(ख) और (ग): जिन 96 शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, उनमें से 37 शहरों ने शीर्ष प्रदर्शन करते हुए अधिकतम अंकों के 80-100% के बीच प्राप्त किए हैं। अन्य 23 शहरों ने संतोषजनक प्रदर्शन करते हुए अधिकतम अंकों के 60-80% के बीच प्राप्त किए हैं। कम प्रदर्शन करने वाले शहरों के प्रदर्शन में सुधार करने के उद्देश्य से, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ शहर जोड़ी (एसएसजे) पहल शुरू की है, जिसके तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले "मेन्टर शहरों" को स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में उनके प्रदर्शन के आधार पर कम प्रदर्शन करने वाले "मेन्टी शहरों" के साथ जोड़ा जाता है।

इसके अलावा, एसबीएम-यू 2.0 के तहत सभी शहरी स्थानीय निकायों को नगरपालिका अपशिष्ट के सभी अंशों के 100 प्रतिशत वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एसबीएम-यू 2.0 के तहत, पूरी मिशन अवधि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल वित्तीय परिव्यय 1,41,600 करोड़ रुपये है, जिसमें 36,465 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है।

*****